



■ सीजेआई ने  
कहा- तत्काल  
मानलों को  
सूचीबद्ध करेगी  
कोर्ट-12



■ देश की प्रमुख  
आठ बुनियादी  
उद्योगों की वृद्धि  
दर घटकर 1.8  
प्रतिशत-12



■ बांगलादेश में  
हादी के बाद एक  
अज्ञ छात्र जेता  
को मारी गई सिर  
में गोली-13



■ वनडे विश्व कप  
2023 के फाइनल में  
हार के बाद संवास  
लेने पर विचार किया  
था : दोहित-14

आज का मौसम  
23.0°  
अधिकतम तापमान  
11.0°  
नव्यूनतम तापमान  
सूर्योदय 07.02  
सूर्यास्त 05.18



# आमृत विचार

| हल्द्वानी |

एक सम्पूर्ण दैनिक अखबार

www.amritvichar.com

2 राज्य | 6 संस्करण

■ लखनऊ ■ बड़ेली ■ कानपुर  
■ मुरादाबाद ■ अयोध्या ■ हल्द्वानी

मंगलवार, 23 दिसंबर 2025, वर्ष 5, अंक 303, पृष्ठ 14 ■ मूल्य 6 रुपये

## वन भूमि पर सभी निर्माण कार्यों पर सुप्रीम रोक

टीर्ष कोर्ट ने उत्तराखण्ड में वन भूमि अतिक्रमण पर लिया स्वतः: संज्ञान

नई दिल्ली, एजेंसी

उच्चतम न्यायालय (सुमित्र कोर्ट) ने उत्तराखण्ड में वन भूमि पर बड़े पैमाने पर हारे रहे अतिक्रमण और अवैध कब्जे के आरोपों को लेकर सोमवार को स्वतः: संज्ञान लेने हुए।

पहाड़ी जिलों में संरक्षित वन भूमि पर अनिवार्य कब्जे से जुड़ा यह मामला अदालत की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष आया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य वागांशी शामिल थे। पीठ ने आरोपों को मंजूरी पर संशोधित याच दरे अब 7.15 प्रतिशत से शुरू होगी। नई दिल्ली एवं 22 दिसंबर से प्रभाव में आ गई है।

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने नए आवास स्ट्रक्चर पर ब्याज दर घटाई

नई दिल्ली। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. ने नए आवास स्ट्रक्चर पर ब्याज दर घटाकर 7.15 प्रतिशत कर रखा।

वन भूमि पर सभी निर्माण कार्यों पर सुप्रीम रोक



■ वन विभाग को  
निर्देश- जहां पहले  
से रिहायशी मकान  
मौजूद नहीं वहां की  
सारी खाली वन  
भूमि अपने कर्जे में  
लौंगिंग जाव  
मांगी रिपोर्ट

अगली सुनवाई पांच जनवरी को निर्धारित अदालत ने दोहराया कि रिहायशी मकानों को छोड़कर सारी खाली वन भूमि वन विभाग के कब्जे में लौंगिंग जाव कर्जी से अगली सुनवाई पांच जनवरी को निर्धारित किया गया। न्यायालय में 19 दिसंबर से 5 जनवरी तक सदियों की छुट्टियां हैं। गोरतालव है कि उत्तराखण्ड में वन भूमि पर अवैध कब्जे का मुदा कई रिपोर्टों में सामने आता रहा है, खासकर वैदेवनाशील पहाड़ी इलाकों में, जहां तेजी से शहरी विस्तार हो रहा है।

पहाड़ी जिलों में संरक्षित वन भूमि पर अनिवार्य कब्जे से जुड़ा यह मामला अदालत की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष आया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य वागांशी शामिल थे। पीठ ने आरोपों को मंजूरी पर संशोधित याच दरे अब 7.15 प्रतिशत से शुरू होगी। नई दिल्ली एवं 22 दिसंबर से प्रभाव में आ गई है।

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने कहा कि मार्कों के लिए नए कर्जे की मंजूरी पर संशोधित याच दरे अब 7.15 प्रतिशत से शुरू होगी। नई दिल्ली एवं 22 दिसंबर से प्रभाव में आ गई है।

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने कहा कि ऐसे सभी के लिए नए कर्जे की मंजूरी पर संशोधित याच दरे अब 7.15 प्रतिशत से शुरू होगी। नई दिल्ली एवं 22 दिसंबर से प्रभाव में आ गई है।

वन भूमि पर सभी निर्माण कार्यों पर सुप्रीम रोक

ने कहा, 'हमें यह देखकर हैरानी हो रही है कि उत्तराखण्ड राज्य और उसके अधिकारी आंखों के सामने वन भूमि पर कब्जा होते देख भी मूक दर्शक बने हुए हैं। इसलिए हम इस मामले में स्वतः: संज्ञान ले रहे हैं।'

न्यायालय ने उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव और प्रधानमंत्री को देखते हुए न्यायिक हस्तक्षेप को देखते हुए न्यायिक हस्तक्षेप वन सरकार को निर्देश दिया कि वे एक तथ्य-जंच समिति गठित करें, जो

जमीनी हालात का आकलन कर अतिक्रमण की सीमा और राज्य प्रशासन की कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। इसके में कोई और वदलावन न हो, इसके लिए खोले जाएं। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान भारत की जांच करायी।

जमीनी हालात का आकलन कर अतिक्रमण की सीमा और राज्य प्रशासन की कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। इसके में कोई और वदलावन न हो, इसके लिए खोले जाएं। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान भारत की जांच करायी।

जमीनी हालात का आकलन कर अतिक्रमण की सीमा और राज्य प्रशासन की कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। इसके में कोई और वदलावन न हो, इसके लिए खोले जाएं। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान भारत की जांच करायी।

जमीनी हालात का आकलन कर अतिक्रमण की सीमा और राज्य प्रशासन की कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। इसके में कोई और वदलावन न हो, इसके लिए खोले जाएं। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान भारत की जांच करायी।

जमीनी हालात का आकलन कर अतिक्रमण की सीमा और राज्य प्रशासन की कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। इसके में कोई और वदलावन न हो, इसके लिए खोले जाएं। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान भारत की जांच करायी।

जमीनी हालात का आकलन कर अतिक्रमण की सीमा और राज्य प्रशासन की कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। इसके में कोई और वदलावन न हो, इसके लिए खोले जाएं। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान भारत की जांच करायी।

जमीनी हालात का आकलन कर अतिक्रमण की सीमा और राज्य प्रशासन की कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। इसके में कोई और वदलावन न हो, इसके लिए खोले जाएं। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान भारत की जांच करायी।

जमीनी हालात का आकलन कर अतिक्रमण की सीमा और राज्य प्रशासन की कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। इसके में कोई और वदलावन न हो, इसके लिए खोले जाएं। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान भारत की जांच करायी।

जमीनी हालात का आकलन कर अतिक्रमण की सीमा और राज्य प्रशासन की कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। इसके में कोई और वदलावन न हो, इसके लिए खोले जाएं। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान भारत की जांच करायी।

जमीनी हालात का आकलन कर अतिक्रमण की सीमा और राज्य प्रशासन की कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। इसके में कोई और वदलावन न हो, इसके लिए खोले जाएं। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान भारत की जांच करायी।

जमीनी हालात का आकलन कर अतिक्रमण की सीमा और राज्य प्रशासन की कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। इसके में कोई और वदलावन न हो, इसके लिए खोले जाएं। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान भारत की जांच करायी।

जमीनी हालात का आकलन कर अतिक्रमण की सीमा और राज्य प्रशासन की कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। इसके में कोई और वदलावन न हो, इसके लिए खोले जाएं। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान भारत की जांच करायी।

जमीनी हालात का आकलन कर अतिक्रमण की सीमा और राज्य प्रशासन की कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। इसके में कोई और वदलावन न हो, इसके लिए खोले जाएं। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान भारत की जांच करायी।

जमीनी हालात का आकलन कर अतिक्रमण की सीमा और राज्य प्रशासन की कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। इसके में कोई और वदलावन न हो, इसके लिए खोले जाएं। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान भारत की जांच करायी।

जमीनी हालात का आकलन कर अतिक्रमण की सीमा और राज्य प्रशासन की कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। इसके में कोई और वदलावन न हो, इसके लिए खोले जाएं। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान भारत की जांच करायी।

जमीनी हालात का आकलन कर अतिक्रमण की सीमा और राज्य प्रशासन की कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। इसके में कोई और वदलावन न हो, इसके लिए खोले जाएं। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान भारत की जांच करायी।

जमीनी हालात का आकलन कर अतिक्रमण की स

## स्टेट ब्रीफ

खड़पीठने मांगा  
सरकार से जवाब

नैनीताल: रुद्रकी के ग्राम नगला इमरती की सार्वजनिक भूमि पर ग्रामीणों द्वारा कब्जा करके अंतर्कामन करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायालय जी. नरेंद्र की खंडपीठने ग्राम सभा को अंतिम जारी करते हुए अपने सरकार से जवाब सप्ताह में जवाब प्रतुल करने को कहा है। मामले की अगती सुनवाई की तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।

## नैनी सैनी का विकास एतिहासिक कदम

पिथौरागढ़: पर्टन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि यह जी की रजत जयती वर्ष में नैनी सैनी एरपोर्ट का विकास राज्य सरकार की एक ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी उपलब्धि है। एयरपोर्ट का चरणबद्ध तरीके से विस्तार पर्याप्त एवं अधिनियमिक कारण विद्या जारी, जिससे भवित्व में बड़े विमानों का संचालन संभव हो सकता। वर्तमान में यह एयरपोर्ट लगभग 70 एकड़ भूमि पर विकसित है, जबकि 72 सीटर विमानों के नियमित संचालन के लिए लगभग 50 से 53 हेक्टेयर अंतिमक भूमि की अवश्यकता होगी। भूमि अधिकारण की प्रक्रिया तीन से अगे बढ़ रही है तथा शीघ्र ही इसे पूर्ण कर लिया जाएगा।

## द्रांसफर पर लगी रोक

नैनीताल: उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने चक्रवर्ती वन भूमि में तीन वर्ष प्रभारीय वनाधिकारी राजीव नैन नीटियाल के व्यापारिक आदेश पर अंतिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैटाणी और नैनीताल, अलोक महरा की खंडपीठने में हुई। कोट्टे ने राज्य सरकार को नैनीताल जारी कर अधिकारी को बखास्त करने के मामले में तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को अपर सचिव वित्त के आदेश पर रोक लगा दी है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैटाणी व न्यायमूर्ति अलोक महरा की खंडपीठने पर्सेस्ट करने के रखरखाव एवं उसकी देखरेख के लिए जारी करने के आदेश का अनुपालन करने के अधिकारी को राज्य सरकार से पूछा है कि पूर्व के आदेश का अनुपालन कर्ता का विद्याकारी में कहा है कि वर्ष 2013 में हाईकोर्ट ने जारीवर मंदिर के लिए एक कमेटी गठित हो, एक सदस्य सर्वो औंड इंडिया का हो, कमेटी में दस सदस्य स्थानीय हो। जिसमें से एक सदस्य को राज्यपाल बाहर फैसले करने के बाद यह सदस्य हो लेकि 12 साल वीत जाने के बाद भी तक न तो कमेटी का गठन हुआ नहीं हो अदेश का अनुपालन। मंदिर की हालत जस की तस बनी हुई है। मंदिर की देखरेख का कोड रिकांड नहीं हो। मंदिर में द्वाएं जाने वाला चारों वाला को बांधे रिकांड नहीं हो। जबकि कुपुरियों की अपी-अपी मनमानी चल रही है। जबकि याचिकार्का में उन्होंने इसकी अराटीआई की प्रति मार्गी तो उनके द्वारा कहा गया कि हम अराटीआई देने के लिए बायी हो है। यह क्योंकि हम एक नियंत्रित राज्य के लिए अपेक्षित हो रही है कि पूर्व के द्वारा जारी विद्याकारी ने उन्होंने इसकी अराटीआई की प्रति मार्गी तो उनके द्वारा कहा गया कि हम अराटीआई देने के लिए बायी हो है। इस आदेश पर पीछे ने अधिकारी के आदेश का अनुपालन करना करवाया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई हेतु 30 मार्च 2026 की तिथि नियत की गई है।

मामले के अनुसार, असिस्टेंट कमिशनर मीनाक्षी त्यागी को 3 अक्टूबर 2025 को चार फर्मों का रजिस्ट्रेशन रोकने में नाकाम रहे और उनके फिल्ड क्लेम की मंजूरी देने के आरोपों पर नैनीताल देने के निकाल दिया गया था। अधिकारी ने कहा कि संबंधित टैक्स अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसने असिस्टेंट कमिशनर के निदेश के बावजूद उन्होंने देने के आरोपों पर नैनीताल देने के निकाल दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि यह विवाहों से पूछताछ का अधिकारी देने के लिए कहा था जिसे जांच अधिकारी अजय कुमार नैनीताल देने के लिए एक कमेटी गठित हो, एक सदस्य सर्वो औंड इंडिया का हो, कमेटी में दस सदस्य स्थानीय हो। जिसमें से एक सदस्य को राज्यपाल बाहर फैसले को सही मानने और शीघ्र करने की विद्याकारी की गई है। इसके बाद यह सदस्य को राज्यपाल बाहर फैसले को सही मानने और शीघ्र करने की विद्याकारी की गई है। इसके बाद यह सदस्य को राज्यपाल बाहर फैसले को सही मानने और शीघ्र करने की विद्याकारी की गई है।



## पूर्व आदेश के अनुपालन को लेकर सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल: हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठने पर वीमा कंपनी द्वारा दायर उस अपील को खारिज कर दिया जासूझे एक मैटिकल स्टोर संचालक की मृत्यु के बाद दिय मुद्रावाची की गणना को बुनीदी दी गई थी। एक पैकिंपेट ने मोटर दुर्घटना द्वारा अधिकारण देहरादून द्वारा साल 2019 में पारित नियांपूर्ण को सही ठहराते हुए देशद्रोही पाकिस्तानी एजेंट दिखाया गया है। मेरे जैसे चेहरा बानकर मेरे चेहरे को देश की जासूझी करते हुए दिखाया गया है। यह वीडियो भाजपा के सोच की भारी पिगवाट का प्रतीक है। वह राजनीति को राजनीति और जनता के सवालों पर नहीं लड़ना चाहते हैं। वह झूट और फेरबे के सहरों राजनीति करना चाहते हैं लेकिन कल डाला हुआ यह वीडियो भाजपा इसे लगाता है। वह किसी भी एंजेसी से जांच कराए, इसमें भाजपा को कोई एतराज नहीं है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठने पर वीमा कंपनी द्वारा दायर उस अपील को खारिज कर दिया जासूझे एक मैटिकल स्टोर संचालक की मृत्यु के बाद दिय मुद्रावाची की गणना को बुनीदी दी गई थी। एक पैकिंपेट ने मोटर दुर्घटना द्वारा अधिकारण देहरादून द्वारा साल 2019 में हाईकोर्ट ने जारीवर मंदिर के लिए एक कमेटी गठित हो, एक सदस्य सर्वो औंड इंडिया का हो, कमेटी में दस सदस्य स्थानीय हो। जिसमें से एक सदस्य को राज्यपाल बाहर फैसले के बाद यह सदस्य हो लेकि 12 साल वीत जाने के बाद भी तक न तो कमेटी का गठन हुआ नहीं हो अदेश का अनुपालन। मंदिर की हालत जस की तस बनी हुई है। मंदिर की देखरेख का कोड रिकांड नहीं हो। मंदिर में द्वाएं जाने वाला चारों वाला को बांधे रिकांड नहीं हो। जबकि कुपुरियों की अपी-अपी मनमानी चल रही है। जबकि याचिकार्का में उन्होंने इसकी अराटीआई देने के लिए बायी हो है। यह क्योंकि हम एक नियंत्रित राज्य के लिए अपेक्षित हो रही है। इस आदेश पर पीछे ने अधिकारण के आदेश का अनुपालन करना करवाया जाए। इस मामले में आलोक महरा की खंडपीठने पर वीमा कंपनी द्वारा जारी विद्याकारी की गई है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठने पर वीमा कंपनी द्वारा दायर उस अपील को खारिज कर दिया जासूझे एक मैटिकल स्टोर संचालक की मृत्यु के बाद दिय मुद्रावाची की गणना को बुनीदी दी गई थी। एक पैकिंपेट ने मोटर दुर्घटना द्वारा अधिकारण देहरादून द्वारा साल 2019 में हाईकोर्ट ने जारीवर मंदिर के लिए एक कमेटी गठित हो, एक सदस्य सर्वो औंड इंडिया का हो, कमेटी में दस सदस्य स्थानीय हो। जिसमें से एक सदस्य को राज्यपाल बाहर फैसले के बाद यह सदस्य हो लेकि 12 साल वीत जाने के बाद भी तक न तो कमेटी का गठन हुआ नहीं हो अदेश का अनुपालन। मंदिर की हालत जस की तस बनी हुई है। मंदिर की देखरेख का कोड रिकांड नहीं हो। मंदिर में द्वाएं जाने वाला चारों वाला को बांधे रिकांड नहीं हो। जबकि कुपुरियों की अपी-अपी मनमानी चल रही है। जबकि याचिकार्का में उन्होंने इसकी अराटीआई देने के लिए बायी हो है। यह क्योंकि हम एक नियंत्रित राज्य के लिए अपेक्षित हो रही है। इस आदेश पर पीछे ने अधिकारण के आदेश का अनुपालन करना करवाया जाए। इस मामले में आलोक महरा की खंडपीठने पर वीमा कंपनी द्वारा जारी विद्याकारी की गई है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठने पर वीमा कंपनी द्वारा दायर उस अपील को खारिज कर दिया जासूझे एक मैटिकल स्टोर संचालक की मृत्यु के बाद दिय मुद्रावाची की गणना को बुनीदी दी गई थी। एक पैकिंपेट ने मोटर दुर्घटना द्वारा अधिकारण देहरादून द्वारा साल 2019 में हाईकोर्ट ने जारीवर मंदिर के लिए एक कमेटी गठित हो, एक सदस्य सर्वो औंड इंडिया का हो, कमेटी में दस सदस्य स्थानीय हो। जिसमें से एक सदस्य को राज्यपाल बाहर फैसले के बाद यह सदस्य हो लेकि 12 साल वीत जाने के बाद भी तक न तो कमेटी का गठन हुआ नहीं हो अदेश का अनुपालन। मंदिर की हालत जस की तस बनी हुई है। मंदिर की देखरेख का कोड रिकांड नहीं हो। मंदिर में द्वाएं जाने वाला चारों वाला को बांधे रिकांड नहीं हो। जबकि कुपुरियों की अपी-अपी मनमानी चल रही है। जबकि याचिकार्का में उन्होंने इसकी अराटीआई देने के लिए बायी हो है। यह क्योंकि हम एक नियंत्रित राज्य के लिए अपेक्षित हो रही है। इस आदेश पर पीछे ने अधिकारण के आदेश का अनुपालन करना करवाया जाए। इस मामले में आलोक महरा की खंडपीठने पर वीमा कंपनी द्वारा जारी विद्याकारी की गई है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठने पर वीमा कंपनी द्वारा दायर उस अपील को खारिज कर दिया जासूझे एक मैटिकल स्टोर संचालक की मृत्यु के बाद दिय मुद्रावाची की गणना को बुनीदी दी गई थी। एक पैकिंपेट ने मोटर दुर्घटना द्वारा अधिकारण देहरादून द्वारा साल 2019 में हाईकोर्ट ने जारीवर मंदिर के लिए एक कमेटी गठित हो, एक सदस्य सर्वो औंड इंडिया का हो, कमेटी में दस सदस्य स्थानीय हो। जिसमें से एक सदस्य को राज्यपाल बाहर फैसले के बाद यह सदस्य हो लेकि 12 साल वीत जाने के बाद भी तक न तो कमेटी का गठन हुआ नहीं हो अदेश का अनुपालन। मंदिर की हालत जस की तस बनी हुई है। मंदिर की देखरेख का कोड रिकांड नहीं हो। मंदिर में द्वाएं जाने वाला चारों वाला को बांधे रिकांड













## ब्रीफ न्यूज

## महाविद्यालय और ग्राम पंचायत के बीच एमओयू

बनवासा: राजकीय महाविद्यालय ने सम्बांधित उत्तरदायित के निवेदन के लिए ग्राम सभा राकेश को अपीकृत किया है। इस मौके पर महाविद्यालय और ग्राम पंचायत के बीच एसओयू किया गया। प्रार्थां अनंद प्रकाश सिंह के नेतृत्व में महाविद्यालय परिवार ने ग्राम सभा का भ्रमण कर विकास की संभावनाओं को देखा। ग्राम सभा राकेश चंद में ग्राम में सहयोग किया। अधियान के अंतर्गत राजकीय आयुर्वेदिक विकित्सालान के विषेषज्ञों के साथ मिलकर ग्रामवासियों के स्वास्थ्य संवर्धन और आयुर्वेदिक जीवन शैली के प्रभाव के लिए कार्ययोजना तैयार की गई। ग्राम प्रधान राकेश चंद ने इस दूरदर्शी पहल का खागद किया।

## गुलदार ने दिन दहाड़े बैल पर किया हमला

चम्पावत: जिला मुख्यालय स्थित दूधपोखरा क्षेत्र में गुलदार ने गांव के पास ही खेत में धास धास चुम्ह रहे बैल पर हमला बोल दिया। ग्रामीणों के शोर मध्याने पर गुलदार की गांव के बाहर के हमले से बैल दुर्घात हाथ लाया हो गया। ग्रामीणों की सुनान के बाद वन विधायक की टीम पशु चिकित्सक को लेकर पौके पर पहुंची और धायल बैल का उत्तराव किया। रंगर बृजमान टट्टा में बताया कि जिला मुख्यालय के दूधपोखरा गांव में सम्मान को दोपहर देव सिंह राकेश के पार गुलदार ने अचानक हमला कर दिया।

## मुख्यमंत्री धामी ने 77.25 करोड़ की योजनाओं की सौगत दी

ताड़ीखेत में 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' योजना के तहत आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में सीएम ने किया प्रतिभाग, जनता से किया संवाद

संवाददाता, राजीखेत

अमृत विचार: अल्मोड़ा जिले के ताड़ीखेत में सोमवार को 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अधियान के तहत आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में मुख्यमंत्री पुक्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। शिविर में बैली संख्या में ग्रामीणों ने जगत दिया। मुख्यमंत्री ने आमजन से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी तथा विभिन्न विधागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। शिविर के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया और कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जिले में कुल 77.25 करोड़ रुपये की लागत की 32 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं रामांगन निर्माण, देवलीखेत, चौनलिया, खिरखेत व भुजान स्थित राजकीय इंटर कॉलेजों में मिनी स्टेडियम निर्माण, सनाना चिंचाई लिफिंग योजना के उच्चीकरण, राजीखेत में एनसीसी प्राउंड/स्टेडियम के लिए एक करोड़ रुपये की 9 योजनाओं का शिलान्वास तथा 29.40 करोड़ रुपये की 23 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के लिए कई समस्याओं की संबंधी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने सुनान राकेश को गदा देकर सम्मानित किया गया।



जन-जन की सरकार जन-जन के द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुक्कर सिंह धामी को गदा देकर सम्मानित किया गया।

भिक्षियार्सेंग विकासखंड में ग्रामांग एवं रामांगन निर्माण, देवलीखेत, चौनलिया, खिरखेत व भुजान स्थित राजकीय इंटर कॉलेजों में मिनी स्टेडियम निर्माण, सनाना चिंचाई लिफिंग योजना के उच्चीकरण, राजीखेत में एनसीसी प्राउंड/स्टेडियम के लिए एक करोड़ रुपये की स्वीकृति, रानीखेत के विस्तारीकरण एवं सौंदर्यीकरण तथा रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में वैलीपैड निर्माण की घोषणा की।

सभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य जनता को उनके क्षेत्र में ही सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए बहुउद्देशीय शिविरों में दर्शन-पूजन किया तथा समस्वती शिशु मंदिर ताड़ीखेत में बच्चों से संवाद किया। इस दौरान विधायक डॉ. प्रमोद नैनवाल, दायित्वधारी कैलाश पांत, अनिल शाही, ब्लॉक प्रमुख बबली मेहरा, डॉ.एम अंशुल सिंह, एसएसपी देवेन्द्र पीचा, सीडीओ रामजीशरण शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष घनश्याम भट्ट को सम्मानित किया गया।

उठाए जा रहे हैं। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने गोलू देवता मंदिर में दर्शन-पूजन किया तथा समस्वती शिशु मंदिर ताड़ीखेत में बच्चों से संवाद किया। इस दौरान विधायक डॉ. प्रमोद नैनवाल, दायित्वधारी कैलाश पांत, अनिल शाही, ब्लॉक प्रमुख बबली मेहरा, डॉ.एम अंशुल सिंह, एसएसपी देवेन्द्र पीचा, सीडीओ रामजीशरण शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष घनश्याम भट्ट को सम्मानित किया गया।

लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से अल्मोड़ा जनपद में ढाई सौ किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है। साथ ही, कोरोडों रुपये की लागत से विभिन्न मोटरसार्मों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है।

लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से अल्मोड़ा जनपद में ढाई सौ किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है। साथ ही, कोरोडों रुपये की लागत से विभिन्न मोटरसार्मों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है।

लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से अल्मोड़ा जनपद में ढाई सौ किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है। साथ ही, कोरोडों रुपये की लागत से विभिन्न मोटरसार्मों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है।

लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से अल्मोड़ा जनपद में ढाई सौ किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है। साथ ही, कोरोडों रुपये की लागत से विभिन्न मोटरसार्मों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है।

लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से अल्मोड़ा जनपद में ढाई सौ किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है। साथ ही, कोरोडों रुपये की लागत से विभिन्न मोटरसार्मों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है।

लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से अल्मोड़ा जनपद में ढाई सौ किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है। साथ ही, कोरोडों रुपये की लागत से विभिन्न मोटरसार्मों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है।

लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से अल्मोड़ा जनपद में ढाई सौ किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है। साथ ही, कोरोडों रुपये की लागत से विभिन्न मोटरसार्मों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है।

लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से अल्मोड़ा जनपद में ढाई सौ किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है। साथ ही, कोरोडों रुपये की लागत से विभिन्न मोटरसार्मों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है।

लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से अल्मोड़ा जनपद में ढाई सौ किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है। साथ ही, कोरोडों रुपये की लागत से विभिन्न मोटरसार्मों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है।

लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से अल्मोड़ा जनपद में ढाई सौ किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है। साथ ही, कोरोडों रुपये की लागत से विभिन्न मोटरसार्मों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है।

लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से अल्मोड़ा जनपद में ढाई सौ किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है। साथ ही, कोरोडों रुपये की लागत से विभिन्न मोटरसार्मों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है।

लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से अल्मोड़ा जनपद में ढाई सौ किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है। साथ ही, कोरोडों रुपये की लागत से विभिन्न मोटरसार्मों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है।

लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से अल्मोड़ा जनपद में ढाई सौ किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है। साथ ही, कोरोडों रुपये की लागत से विभिन्न मोटरसार्मों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है।

लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से अल्मोड़ा जनपद में ढाई सौ किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है। साथ ही, कोरोडों रुपये की लागत से विभिन्न मोटरसार्मों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है।

लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से अल्मोड़ा जनपद में ढाई सौ किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है। साथ ही, कोरोडों रुपये की लागत से विभिन्न मोटरसार्मों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है।

लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से अल्मोड़ा जनपद में ढाई सौ किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है। साथ ही, कोरोडों रुपये की लागत से विभिन्न मोटरसार्मों का निर्माण एवं नवीनीकरण की घोषणा है।

लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से अल्मोड़ा





वनस्पति तेल तिलहन: तुलसी 2550, राज श्री 1800, फॉर्मूल कि. 2245, रविन्द्रा 2445, फॉर्मूल 13 किंग्रा 1975, जय जवान 1990, सर्वेन 2020, सूरज 1990, अंवरस 1875, लक्ष्मी 1910, गुहाणी 13 किंग्रा 1870, कलासिंह 2155, मर 2185, वर्षा 2135, लू 2100, आपीवां मरस्ट 2330, खासिंह 2505

किरान: हड्डी निजामाबाद 17000, जीरा 24500, लाल मिर्ज 14000-18000, धनिया 9400-12000, अंजवायन 13500-20000, मेथी 6000-8000 सौफ़ 9000-11000, सोट 31000, प्रतिक्रिया 1000-1000, बदाम 780-1080, काजू 2 पीस 840, किसमिस पीली 300-400, मस्खा 800-1100 चावल (प्रक्रिया): डबल चावी सेला 9600, स्पाइस 6500, शरवती कच्ची 4850, शब्दी रस्टी 5200, मंसूरी 4000, महवूल सेला 4050, गोरी रस्टैल 7400, राजमैंग 6850, हरी पाती (1 किंग्रा, 5 किंग्रा) 10100, हरी पाती नेतुरल 9100, जेनिया 8400, गौरकौसी 7400, सूमी 4000, गोल्डन सेला 7900, मंसूरी पन्थट 4350, लाडली 4000

दाल दलहन: मुग दाल इंदौर 9800, मूंग धाव 10000, रोटाम चिंवा 12000-13400, राजमा भूटान नया 10100, मलका काली 7250-7450 मलका दाल 7350-9200, मलका छोटी 7250, दाल उड़ बिलासपुर 8000-8800, मंसूर दाल छोटी 10000-11600, दाल उड़ दिल्ली 10300, उड़ दाल सातुर दिल्ली 9900, उड़ दोहा इंदौर 11800, उड़ दोहा 9800-10400, जाना काला 1050, दाल चान 7250, दाल चान मैटी 7400, मलका विदेशी 7300, रूपधिको बेसा 7800, चना अकोला 6600, डबरा 6700-8800, सच्चा हीरा 8500, मोटा हीरा 9900, अरहर गोला मोटा 7700, अरहर पटका मोटा 8000, अरहर कांसा मोटा 8500, अरहर पटका छोटा 10000-10600, अरहर कंटी 11000 चीनी: पीलीभीत 4280, बहड़ी 4220

चावल: शरबती- 3400, मसूरी- 950, बासमती- 5300, परमल- 1000 दाल दलहन: काला चान- 3200, साबुत चान चान- 2900, मूंग सातुर- 4000, राजमा- 8200-12100, दाल उड़- 6400, साबुत मसूर दाल- 3600, मसूर दाल- 3200, उड़ दाल सातुर- 5100, काबूली चान- 8400, अरहर दाल- 10200, लोबिया/करमानी- 1400

# किसानों-एमएसएमई के हितों को दिया महत्व

डेयरी, सब्जियां, चीनी, तांबा, एल्युमिनियम पर न्यूजीलैंड को भारत की ओर से नहीं दी जाएगी शुल्क दियायत

## भारत-न्यूजीलैंड एफटीए

नई दिल्ली, एजेंसी

भारत ने न्यूजीलैंड के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में किसानों और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के हितों को प्राथमिकता देते हुए डेयरी, पशु उत्पाद, सब्जियां, चीनी, तांबा और एल्युमिनियम जैसे कई संवेदनशील क्षेत्र में कोई भी शुल्क दियायत नहीं देने का फैसला किया है। दोनों देशों ने सोमवार को एफटीए वार्ता पूरी होने और तीन महीनों के भीतर न्यूजीलैंड पर हस्ताक्षर होने की घोषणा की।

इस समझौते के अगले वर्ष लगू हो जाने की उम्मीद है। समझौते के तहत जिन उत्पादों को शुल्क दियायत सची से बाहर रखा गया है, उनमें डेयरी उत्पाद (दध, क्रीम, दही, पीनर), पशु उत्पाद (भैंड के मांस को छोड़कर), सब्जी उत्पाद (प्याज, चना, मटर, मक्का), चीनी, कृतिम शहद तथा पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीव आश्रित वसा एवं तेल शामिल हैं। इनके अलावा हथियार और गोला-बारूद, रत्न एवं आधिकारी वस्तुओं पर उपसे संविधान वस्तुओं पर भी भारत, न्यूजीलैंड को किसी तरह की शुल्क दियायत नहीं देगा। हालांकि, कुछ कृषि उत्पादों में भारत ने सीमित बाजार पहुंच दी है, लेकिन इसे 'शुल्क दर कोटा' (टीआरक्यू) और 'न्यूनतम आयात मूल्य' (एमआई) के साथ जोड़ा गया है। इनमें मनुका शहद, सेब, कीवी, फल और देशों में इस्तेमाल होने वाला एल्युमिनियम शामिल है। वर्तमान में न्यूजीलैंड के खास उत्पाद मनुका शहद पर 46 प्रतिशत शुल्क लगता है।

समझौते के तहत भारत इस शहद के सालाना 200 टन तक आयात पर रियायत देगा, जिसमें एमआईपी 20 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम तथ



भारत-न्यूजीलैंड के बीच हुए एफटीए की जानकारी देते केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल,

## द्विपक्षीय व्यापार समझौते की मुख्य बातें

भारत के 100% निर्यात पर शूल्क दियायत की प्रक्रिया की जिसके द्वारा भारत-न्यूजीलैंड द्विपक्षीय व्यापार दोनों वार्ता पूरी होने की घोषणा की जाएगी। एफटीए के लिए अस्थायी रोजार दोर्याए में भारत-न्यूजीलैंड द्विपक्षीय व्यापार की घोषणा की जाएगी। यह बाजार पहुंच भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे वस्तु, परियान, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आधुनिक, रहस्याल्प, इंजिनियरिंग सामान तथा भोजन वाहन की प्रतिस्थापन की बहती है।

किसी भी व्यक्तिके देश के साथ सबसे तेजी से बदलना हुआ था यह मूल्य व्यापार तथा उत्पादन की घोषणा की जाएगी।

नियर्यातों के लिए वर्ष शामिल की जाएगी।

भारत-न्यूजीलैंड द्विपक्षीय व्यापार की घोषणा की जाएगी।

यह बाजार पहुंच भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे वस्तु, परियान, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आधुनिक, रहस्याल्प, इंजिनियरिंग सामान तथा भोजन वाहन की प्रतिस्थापन की बहती है।

यह बाजार पहुंच भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे वस्तु, परियान, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आधुनिक, रहस्याल्प, इंजिनियरिंग सामान तथा भोजन वाहन की प्रतिस्थापन की बहती है।

यह बाजार पहुंच भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे वस्तु, परियान, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आधुनिक, रहस्याल्प, इंजिनियरिंग सामान तथा भोजन वाहन की प्रतिस्थापन की बहती है।

यह बाजार पहुंच भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे वस्तु, परियान, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आधुनिक, रहस्याल्प, इंजिनियरिंग सामान तथा भोजन वाहन की प्रतिस्थापन की बहती है।

यह बाजार पहुंच भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे वस्तु, परियान, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आधुनिक, रहस्याल्प, इंजिनियरिंग सामान तथा भोजन वाहन की प्रतिस्थापन की बहती है।

यह बाजार पहुंच भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे वस्तु, परियान, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आधुनिक, रहस्याल्प, इंजिनियरिंग सामान तथा भोजन वाहन की प्रतिस्थापन की बहती है।

यह बाजार पहुंच भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे वस्तु, परियान, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आधुनिक, रहस्याल्प, इंजिनियरिंग सामान तथा भोजन वाहन की प्रतिस्थापन की बहती है।

यह बाजार पहुंच भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे वस्तु, परियान, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आधुनिक, रहस्याल्प, इंजिनियरिंग सामान तथा भोजन वाहन की प्रतिस्थापन की बहती है।

यह बाजार पहुंच भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे वस्तु, परियान, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आधुनिक, रहस्याल्प, इंजिनियरिंग सामान तथा भोजन वाहन की प्रतिस्थापन की बहती है।

यह बाजार पहुंच भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे वस्तु, परियान, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आधुनिक, रहस्याल्प, इंजिनियरिंग सामान तथा भोजन वाहन की प्रतिस्थापन की बहती है।

यह बाजार पहुंच भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे वस्तु, परियान, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आधुनिक, रहस्याल्प, इंजिनियरिंग सामान तथा भोजन वाहन की प्रतिस्थापन की बहती है।

यह बाजार पहुंच भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे वस्तु, परियान, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आधुनिक, रहस्याल्प, इंजिनियरिंग सामान तथा भोजन वाहन की प्रतिस्थापन की बहती है।

यह बाजार पहुंच भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे वस्तु, परियान, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आधुनिक, रहस्याल्प, इंजिनियरिंग सामान तथा भोजन वाहन की प्रतिस्थापन की बहती है।

यह बाजार पहुंच भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे वस्तु, परियान, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आधुनिक, रहस्याल्प, इंजिनियरिंग सामान तथा भोजन वाहन की प्रतिस्थापन की बहती है।



